नं. जेड-14014/1/2021-जीसी एण्ड पार्लि. (ई-3010921)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 18.08.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: जुलाई, 2023 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार - के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को जुलाई, 2023 माह के लिए भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोक्त।

(अर्जुन राणा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044653

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी माननीय सदस्य

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. भारत के माननीय राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के माननीय प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
6. सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।
7. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।

8. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. सचिव, विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली।
12. सचिव, खान मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
14. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
15. सचिव, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
16. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।
17. सचिव, व्यय विभाग, नई दिल्ली।
18. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।
19. सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
20. सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
22. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी), भूमि संसाधन विभाग, को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीया राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथाउपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के निजी सचिव।
3. माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास तथा इस्पात) के निजी सचिव।

जुलाई, 2023 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार - के संबंध में।

1. भूमि संसाधन विभाग ने भारत के माननीय राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 18 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन, में ***भूमि सम्मान 2023*** कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भूमि प्रबंधन और प्रशासन का केन्द्र-डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)के मुख्य घटकों में सेचुरेशन प्राप्त करने वाले 09 राज्यों के राजस्व सचिवों और 68 जिलों के कलेक्टरों को उनकी टीमों के साथ "भूमि सम्मान" प्रदान किया। यह आयोजन राज्यों के उन राजस्व और रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था जिन्होनें भारत के माननीय राष्ट्रपति से अपने उत्कृष्ट प्रदर्शनों के लिए पिछले 75 वर्षों में पहली बार "भूमि सम्मान" प्राप्त किया। इस प्रकार, वास्तव में भूमि सम्मान को संस्थागत रूप देने के लिए यह एक ऐतिहासिक वर्ष रहा।

2. यह उल्लेखनीय है कि माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने दिनांक 23 फरवरी, 2022 को पश्च-बजट वेबिनार में परिकल्पना की थी कि सभी सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं के योजना घटकों को सौ प्रतिशत लक्ष्य तक इस तरह पूरा किया जाए कि कोई भी नागरिक इसके लाभ से वंचित न रहे। दिनांक 03 जुलाई, 2023 को मंत्री परिषद की बैठक में, माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने योजनाओं के घटकों में सौ प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की अवश्यकता को दोहराया था। इस दिशा में, इस विभाग ने डीआईएलआरएमपी के छह मुख्य घटकों में प्रदर्शन आधारित ग्रेडिंग शुरू की थी। डीआईएलआरएमपी की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर यथा प्रदर्शित और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा, यथा सूचित जिलों के प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग की गई थी। प्लेटिनम ग्रेडिंग प्रमाणपत्र उन जिलों को प्रदान किए गए जिन्होंने डीआईएलआरएमपी के संबंधित मुख्य घटकों में पूर्ण सैचुरेशन (saturation) अर्थात 100% लक्ष्य पूरा कर लिया है।

3. *'जीवन-यापन में सुगमता का संवर्धन'* विषय पर **मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी बैठक** पर दूसरी कार्यशाला 15 जुलाई, 2023 को सचिव, भूमि संसाधन विभाग और सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सह-अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन में संयुक्त सचिव (भूमि विनियमन), भूमि संसाधन विभाग ने भूमि, संपत्ति और नामांतरण संबंधी दो सत्रों का संचालन किया।

4. **राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस)** के एक भाग के रूप में, तेलंगाना राज्य ने माह जुलाई, 2023 से यूजर इंटरफेस (यूआई) के माध्यम से एनजीडीआरएस के राष्ट्रीय पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण संबंधी जानकारी साझा करना शुरू कर दिया है। दिनांक 31 जुलाई, 2023 की स्थिति के अनुसार, 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनजीडीआरएस को शुरू किया गया है; जबकि 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने यूजर

इंटरफेस/एपीआई के माध्यम से एनजीडीआरएस के राष्ट्रीय पोर्टल पर डेटा साझा करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार, कुल 30 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनजीडीआरएस-ई-रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के तहत शामिल हैं।

5. हिंगोनिया गौशाला, जयपुर, राजस्थान में कैक्टस बायोमास से **बायो-गैस के उत्पादन के लिए प्रस्तावित कैक्टस वृक्षारोपण** की योजना पर चर्चा करने के लिए दिनांक 12 जुलाई 2023 को एसएलएनए, राजस्थान और अन्य हितधारकों के साथ संयुक्त सचिव (वाटरशेड प्रबंधन) द्वारा एक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी। कार्बन पृथक्करण, कार्बन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट से किसान कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएम) की अध्यक्षता में दिनांक 14 जुलाई, 2023 को हाइब्रिड मोड पर एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और ईशा फाउंडेशन, कोयंबटूर के अधिकारियों ने भाग लिया।

6. भूमि संसाधन विभाग ने दिनांक 21 और 28 जुलाई, 2023 को शिवाजी स्टेडियम कार्यालय परिसर में 'रिजुव वेलनेस सेंटर' में योग सत्र आयोजित किया, जिसमें विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों ने भाग लिया। इसके अलावा, योग विशेषज्ञों के माध्यम से नियमित कार्यकलाप के एक भाग के रूप में अब हर महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार (दोपहर) को योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

7. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के तहत, कुल 6382 {8214 (स्वीकृत) - 1832 (राज्यों को अंतरित)} परियोजनाओं में से अब तक 6376 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अभी तक 5942 परियोजनाओं की एंड लाइन मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं।

8. **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के विभिन्न** घटकों की प्रगति (संचयी) की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

i. 6,22,672 गांवों के भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।
ii. 4,963 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में रजिस्ट्रीकरण का कंप्यूटरीकरण पूरा किया गया।
iii. 1,30,65,074 भूकर मानचित्रों/एफएमबी/टिप्पनों का डिजिटलीकरण पूरा किया गया।
iv. 4,288 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों का भूमि अभिलेखों के साथ एकीकरण पूरा किया गया।
v. 3,326 तहसीलों में आधुनिक अभिलेख कक्षों की स्थापना पूरी की गई।